

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
डाक विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 532  
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

संदर्भ एवं विशिष्ट वर्चुअल पते के लिए डिजिटल हब (धुव) नीति

532. श्री भर्तृहरि महताब :

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

श्री गोडम नागेश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) संदर्भ एवं विशिष्ट वर्चुअल पते के लिए डिजिटल हब (धुव) के प्रमुख उद्देश्यों और घटकों का ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भारत के डिजिटल संचार अवसंरचना को किस प्रकार सुदृढ़ करना है;
- (ख) परियोजना धुव किस प्रकार स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता करेगी और दूरसंचार एवं डिजिटल क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों में योगदान देगी;
- (ग) धुव परियोजना के कार्यान्वयन के अपेक्षित परिणाम और समय-सीमा क्या हैं और इसके क्रियान्वयन से वंचित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा; और
- (घ) पालघर जिले के ग्रामीण क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कार्यान्वित और कार्यान्वित किए जाने वाले संदर्भ एवं विशिष्ट वर्चुअल पते हेतु डिजिटल हब का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

- (क) इस पहल का उद्देश्य भारत में पतों की संरचना और प्रबंधन के तरीके को बेहतर बनाना है। यह प्रणाली लगभग 4 मीटर×4 मीटर के जियो-कोडेड ग्रिड सिस्टम नामतः डिजिपिन का उपयोग कर लोकेशन को विशिष्ट कोड प्रदान कर कार्य करती है। इससे लोकेशन की सटीकता में उल्लेखनीय सुधार होता है और लोकेशन की सटीक पहचान संभव होती है।

इसके अतिरिक्त, 'डिजिटल पता' लेयर उपयोगकर्ताओं को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे डिजिपिन को वर्णनात्मक जानकारी जैसे मकान संख्या, सड़क के नाम आदि के साथ संयोजित कर व्यक्तिगत पता लेबल जनरेट कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण पते के उपयोग को सरल बनाता है, सटीकता बढ़ाता है और लोकेशन के संयुक्त उपयोग को सरल बनाने की सुविधा प्रदान करता है और अंततः एक मजबूत डिजिटल पता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

संघीय और अंतर-प्रचालनीय डिजाइन के साथ संकल्पित यह पहल प्रत्येक लोकेशन को डिजिटल रूप से एड्रेसेबल बनाती है, जिससे डाक, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में विशेषकर दूरदराज और सेवा से वंचित क्षेत्रों में सेवा डिलिवरी एवं नियोजन को सुदृढ़ किया जा सके।

(ख) यह पहल पूर्ण रूप से भारत में विकसित जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देती है। एक ओपन-सोर्स समाधान के रूप में, यह पता-आधारित समाधानों में स्वदेशी पहल को प्रोत्साहित करता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(ग) पहचाने गए परिणामों में डिजिटल समावेशन में वृद्धि, संसाधन नियोजन में सुधार, वितरण लागत में कमी तथा डाक, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में अधिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं - जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों को लाभांवित करेंगी।

(घ) इस संबंध में, नीतिगत दस्तावेज़ का मसौदा, हितधारकों के परामर्श के लिए परिचालित किया गया है। परियोजना प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (पीओसी) चरण में है।

\*\*\*\*\*